पहला कॉलम

चीन के तटरक्षक बल के जहाजों ने जापान के समुद्री इलाके में प्रवेश किया

» **टोक्यो।** चीन के तटरक्षक बल के दो जहाज क्यूशू द्वीप के दक्षिण-पश्चिम इलाके के पास जापान के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अधिकारियों ने यहां इसकी पुष्टि की। समाचार एजेंसी एफे न्यूज के अनुसार, चीन के ये दो जहाज शनिवार को कोरिया स्ट्रेट में स्थित सूशीमा और ओकिनोशीमा द्वीपों के पास जापान के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जापान के तटरक्षक बल ने रेडियो की मदद से जहाजों को लौटने के लिए कहा। हालांकि बल ने इसे एक गैरकानूनी अतिक्रमण नहीं माना है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि के अंतर्गत जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्थानीय नियमों के अनुसार प्रादेशिक समुद्री क्षेत्रों से गुजरने की अनुमति है। यह पहली बार है जब चीन के जहाजों ने इस इलाके में प्रवेश किया है।

जाधव पर जल्द फैसला लेंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख

» **इस्लामाबाद।** पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की दया याचिका पर जल्द ही फैसला लेंगे। रविवार को इसकी घोषणा की गई। पाकिस्तान के समाचार चैनल जीयोन्यूज के अनुसार, जाधव मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना प्रमुख मामले की सुनवाई की समीक्षा कर रहे हैं और जाधव की दया याचिका को प्राथमिकता देते हुए जल्द ही कोई फैसला लेंगे। वहीं रेडियो पाकिस्तान ने प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि जनरल बाजवा जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला लेंगे। सरकारी रेडियो चैनल ने रक्षा प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि फैसला न्याय पर आधारित होगा। जासूसी करने और बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

ब्रिटेन में तेजाब से होने वाले हमले संबंधी कानून की समीक्षा होगी

» **लंदन।** इंग्लैंड एवं वेल्स में तेजाब से हमला करने वालों की सजा को और बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर की समीक्षा हो सकती है। यह इस तरह के हमलों की संख्या में वृद्धि को को देखते हुए किया जा सकता है। ब्रिटेन की गृह मंत्री अंबर रुड ने द संडे टाइम्स से कहा कि अपराधियों को कानून की संपूर्ण शक्ति महसूस होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन भर की कैद तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए ही होकर रह जाए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को ब्रिटेन के निचले सदन हॉउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को तेजाब हमलों पर बहस करनी है। इस समीक्षा में प्रचलित कानूनों, पुलिस की प्रतिक्रिया, जेल भेजे गए अपराधियों, लोगों की इन हानिकारक पदार्थों तक पहुंच कैसे हुई और तेजाब हमले के पीड़ितों को सहायता आदि को देखा जाएगा।

कतर मसले पर बात के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे

» **रियाद।** फ्रांस के विदेश मंत्री जीन युवेस ली ड्रायन कतर संकट को सुलझाने में मदद करने के प्रयास के तहत सऊदी अरब पहुंचे हैं। ली ड्रायन ने अपने सऊदी समकक्ष अदेल अल-जुबेर के साथ रविवार को एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन में कहा, फ्रांस उन प्रतिबंधों को जल्द से जल्द खत्म करने का आग्रह करता है जिसके कारण इन देशों से संबंध रखने वाले परिवार व छात्र अलग-अलग हो गए हैं। ली ड्रायन ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र से वार्ता के माध्यम से इस संकट को सुलझाने का आग्रह किया। रियाद की यात्रा के बाद ली ड्रायन मध्यस्थता का प्रयास करने के लिए कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान अल-जुबेर ने दावा किया कि वह सबूत प्रदान कर सकते हैं कि कतर ने 2013 के रियाद समझौते और 2014 रियाद सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट का उल्लंघन किया था, जिसका उद्देश्य खाड़ी देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना था।

एर्दोगन बोले, तुर्की को लोगों ने अपनी जान देकर बचाया

» **अंकारा।** तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एदोर्गन ने असफल सैन्य तख्तापलट की पहली बरसी पर इस्तांबुल में आयोजित एक रैली के दौरान लाखों लोगों को संबोधित किया। एदोर्गन ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, उस रात लोगों के हाथों में बंदूकें नहीं थीं, उनके हाथों में झंडे थे और सबसे अहम उनके साथ उनका विश्वास था। एदोर्गन ने कहा, मैं अपने देश के उन सभी लोगों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा की। उन्होंने कहा कि 250 लोगों ने अपनी जान देकर देश का भविष्य सुरक्षित रखा। राष्ट्रपति एदोर्गन ने इसके बाद इस्तांबुल ब्रिज पर शहीद मेमोरियल का भी उद्घाटन किया। इस पुल का नाम बदलकर मार्टियर्स ऑफ जुलाई 15 कर दिया गया है। तुर्की की सरकार ने नाकाम तख्तापलट के बाद लगभग डेढ़ लाख लोगों को बर्खास्त किया था। सरकार के अनुसार वह तख्तापलट का समर्थन करने वालों को दंडित कर रही है। तुर्की ने इस तख्तापलट के असफल प्रयास के लिए मुस्लिम धर्मगुरु फतेउल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराया था।

प्रवेश पर प्रतिबंध ! संघीय न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

ट्रंप प्रशासन ने यात्रा प्रतिबंध पर संघीय कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

« वाशिंगटन। एजेंसी

अमरीका के ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम बहुल 6 देशों से आने वाले यात्रियों के अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले को कमजोर करने वाले संघीय न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संघीय न्यायाधीश ने अपने फैसले में अमरीकी नागरिकों के परिवारों के संबंधियों की उस सूची में विस्तार किया है, जिसका वीजा प्रार्थी अमरीका आने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्याय मंत्रालय ने कल शाम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हवाई के संघीय न्यायाधीश के इस सप्ताह सुनाए उस फैसले को बदलने का अनुरोध किया, जिसमें यात्रा प्रतिबंध से प्रभावित लोगों की संख्या सीमित करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश है लेकिन वह आपातकालीन मामलों की सुनवाई कर सकता है। अमरीका जिला न्यायाधीश डेरिक वाट्सन ने इस सप्ताह आदेश दिया था कि ट्रंप प्रशासन अमरीका में रह रहे लोगों के दादा-दादी, नाना-नानी, नाती-नातिन, पोता-पोती, बहनोई, साला, जेठ, देवर, ननद, देवरानी, जेठानी, भाभी, चाचा-चाची, मामा-मामी, भांजा-भांजी, भतीजा-भतीजी आदि और रिश्ते के भाई बहनों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाए। वाटसन ने अपने आदेश में कहा, उदाहरणार्थ यह समझने वाली बात है कि निकट संबंधियों में दादा-दादी, नाना-नानी भी शामिल होते हैं। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि सरकार उन शरणार्थियों को बाहर नहीं कर सकती जिन्हें अमरीका में पुनर्वास एजेंसी से औपचारिक आश्वासन मिला है। अटार्नी जनरल जेफ सेशंस ने हवाई की अदालत के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि जिला कोर्ट ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो कार्यकारी शाखा के क्षेत्र में आते हैं, इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है, कार्रवाई में देरी की है, अव्यवस्था की स्थिति पैदा की है और अधिकारों के विभाजन के उचित सम्मान का उल्लंघन किया है।

फ्रेंच राष्ट्रपति की पत्नी की फिगर पर ये कमेंट कर फिर फंसे ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं लेकिन इस बार ट्रंप अपने नए कमेंट के कारण सुर्खियों में हैं। दरअसल फ्रांस पहुंचे ट्रंप ने गुरुवार को फ्रेंच राष्ट्रपति की पत्नी के फिगर की तारीफ की थी। ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई और फ्रेंच गर्वमेंट के फेसबुक पेज पर भी पोस्ट की गई। इस वीडियो को लेकर ट्रंप की काफी आलोचना हुई । हालांकि, व्हाइट हाऊस ने इस मुद्दे पर कोई भी कमेंट करने से इंकार किया है। जानकारी मुताबिक, पेरिस पहुंचे ट्रंप ने फ्रेंच राष्ट्रपति की पत्नी ब्रिजिट से कहा, आपकी फिगर बेहद अछी है। खूबसूरत। ट्रंप के साथ ही फ्रेंच राष्ट्रपति और अमरीका की फर्स्ट लेडी मलेनिया ट्रंप भी खड़ी थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रंप के इस कमेंट को सेक्सिस्ट करार देते हुए उसकी निंदा की है। इतना ही नहीं फ्रीलांस वीडियो प्रोड्यूसर और नारीवादी व लैंगिक मुद्दों पर लिखने वाले राइटर ऐलेक्स बर्ग ने ट्विटर पर लिखा, ट्रंप का फ्रांस की प्रथम महिला को कहना, आपकी फिगर बहुत अछी है, प्रशंसा और यौन दुर्व्यवहार के बीच के फर्क को भूलने वाले पुरुषों का उदाहरण है।

विकीलीक्स संस्थापक ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमे का समर्थन किया

विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ ट्विटर उपभोक्ताओं द्वारा दायर मुकदमे का समर्थन किया है। ट्रंप ने इन ट्विटर उपभोक्ताओं को पिछले सप्ताह ब्लॉक कर दिया था। असांज ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, मैं ट्रंप के खिलाफ मुकदमे का समर्थन करता हूं। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा राजनीतिक टिप्पणियों को ब्लॉक करना संवैधानिक उल्लंघन है। असांज ने कहा कि इसमें एकमात्र अपवाद हो सकता है, जब उपभोक्ता एक ही टिप्पणी बार-बार करता रहे, जिससे अन्य लोगों को अपनी बात रखने का मौका ही न मिले। पिछले सप्ताह समूह ने तर्क दिया था कि ट्रंप का ट्विटर अकाउंट एक जनमंच के समान है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी के तौर पर वह लोगों को रोक नहीं सकते। ब्लॉक्ड ट्विटर उपभोक्ताओं ने ट्रंप, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर और व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया निदेशक डैन स्काविनो के खिलाफ मंगलवार को मुदकमा दायर किया था। समूह ने दावा किया है कि राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ताओं को सोशल नेटवर्क पर ब्लॉक करना असंवैधानिक है।

भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित :सर्वेक्षण

« वाशिंगटन। एजेंसी

भारतीय विद्यार्थियों को अमेरिका में अपनी संभावित पढ़ाई को लेकर बड़ी चिंता है। उनमें से बड़ी संख्या में छात्रों को अपनी सुरक्षा और उन्हें सहज रुप में लिये जाने की चिंता सता रही है।एक ताजा सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजूकेशन (आईआईए) का मानना है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने छह मुस्लिम बहुत देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को जून के अपने फैसले में अस्थायी रुप से सही ठहराया लेकिन इसका अंतिम फैसला क्या होगा इसको लेकर उनके दिमाग में चिंता बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार लाखों अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिका में ऊंची शिक्षा ले रहे हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 36 अरब डॉलर से अधिक का योगदान कर रहे हैं, ऐसे में काफी कुछ दांव पर लगा है। आईआईई छात्रवृति को बढ़ावा देकर, अर्थव्यवस्था में योगदान कर तथा मौके उपलब्ध कराकर शांतिपूर्ण और समान समाज के निर्माण की दिशा में काम करने वाला गैर लाभकारी संगठन है। आईआईई ने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे पश्चिम एशिया और भारत के विद्यार्थियों के दाखिले के संबंध में शीर्ष संस्थागत चिंता को दर्शाते हैं। 31प्रतिशत शैक्षणिक संस्थाओं को चिंता है कि प्रवेश की पेशकश स्वीकार करने वाले पश्चिम एशिया के विद्यार्थी शायद कैंपस नहीं पहुंचे।

इंडोनेशिया ने विवादित दक्षिण चीन सागर के हिस्से का नया नाम रखा

» **जकार्ता।** इंडोनेशिया अब विवादित दक्षिण चीन सागर के उत्तरी हिस्सों में पड़ने वाले अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को उत्तर नतुना सागर कहेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया ने यह कदम इस समुद्री क्षेत्र में चीन द्वारा क्षेत्र विस्तार की महत्वाकांक्षाओं के प्रतिरोध में उठाया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, जकार्ता में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में समुद्री संप्रभुता मामलों के उप मंत्री आरिफ हवास ओएग्रोसेनो ने इस क्षेत्र के बदले हुए नाम के साथ एक नए मानचित्र का अनावरण किया। ओएग्रोसेनो ने इंडोनेशिया सरकारी समाचार एजेंसी अंतरा से कहा, हमें समुद्र के नाम को लगातार अपडेट रखने और सीमाओं के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह जानने का मौका देगी कि वे किसके क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। इंडोनेशिया द्वारा नाम में परिवर्तन वाला यह क्षेत्र चीन द्वारा बनाए गए विवादित नाइन डैश लाइन क्षेत्र में पड़ता है। यह चीन के द्वीपीय प्रांत हैनान के दक्षिण और पूर्व के सैंकड़ों मीटर तक फैला हुआ है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन इस विवादित समुद्र के पूरे क्षेत्र पर दावा करता है, लेकिन वियतनाम, ताइवान, फिलीपीन्स, ब्रुनेई और मलेशिया सभी अपने अपने समुद्री किनारों के पास वाले हिस्से पर अपना दावा करते हैं।

अमेरिकी महिला सांसदों का प्रदर्शन, हमें स्लीवलेस कपड़े पहनने से न रोका जाए

« वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका में कम से कम 30 महिला सांसदों ने बिना बाजू वाले कपड़े पहन कर खुले बाजू के अधिकार (स्लीवलेस कपड़े) के लिए प्रदर्शन किया। सांसदों ने हाउस चेंबर की सीमा से सटी स्पीकर की लॉबी में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। यह वह स्थान है जहां रिपोर्टर साक्षात्कार लेते हैं। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहां महिला रिपोर्टरों और सांसदों को ढकी बाजू वाले कपडे पहन कर आना अनिवार्य है । पुरुषों के लिए जैकेट और टाई पहनना अनिवार्य है। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद लिंडा सांचेज ने कुछ वर्षों पूर्व तक महिला शौचालय नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा, ये नियम पुरातन काल के हैं---अगर हम परंपरा का पालन करते तो इस फ्लोर में महिला शौचालय नहीं होता। हाल ही में सीबीएस न्यूज रिपोर्ट में एक युवा महिला पत्रकार के बिना बाजू के कपड़े पहनने के कारण उसे कमरे में नहीं जाने देने की रिपोर्ट ने खूब सुर्खी बटोरी थी और साथ ही एक नई बहस को जन्म दिया था। बुधवार को रिपब्लिकन सांसद मार्था मैकसेली ने कहा था, इससे पहले कि मैं वापस जाऊं मैं कहना चाहती हूं कि मैं यहां अपने प्रोफेशनल ड्रेस में हूं जो कि बिना बाजू की है और शूज आगे से खुले हुए हैं। इसके साथ ही स्पीकर महोदय मैं वापस जाती हूं। मैकसेली की इस टिप्पणी ने ही प्रदर्शन की शुरुआत की।

यरूशलम के धार्मिक स्थल पर हमले के बाद इस्रायली सेना हमास का अगला निशाना

» **गाजा सिटी।** गाजा के उग्रवादी हमास शासकों ने हमले के कारण इस्रायल के एक धार्मिक स्थल के बंद होने के बाद फलस्तीनियों से यरूशलम में इस्राइली बलों पर हमले का आह्वान किया है। हमास के प्रवक्ता फावजी बरहौम ने फलस्तीनी विद्रोह से इस्राइली सेना और पश्चिमी तट पर बस्तियों में रहने वालों को निशाना बनाने का आह्वान किया है। बयान में हमास ने उस धार्मिक स्थल को बंद किए जाने को धार्मिक युद्ध करार दिया है जिसे मुस्लिम नोबेल सैंक्चुअरी और यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। इस्राइल में शुक्रवार को तीन फलस्तीनी हमलावरों ने गोलीबारी की थी। इसमें दो इस्राइली पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। हमलावर इस्राइल के मुस्लिम नागरिक थे। शनिवार को व्हाइट हाउस ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। हमास ने इस हमले का जश्न मनाने के लिए एक रैली भी निकाली थी। मुस्लिम प्रशासित इस धार्मिक स्थल के प्रति मुस्लिम और यहूदी दोनों गहरी आस्था रखते हैं।

जेआईटी ने शरीफ के खिलाफ 15 मामले फिर से खोलने की सिफारिश की

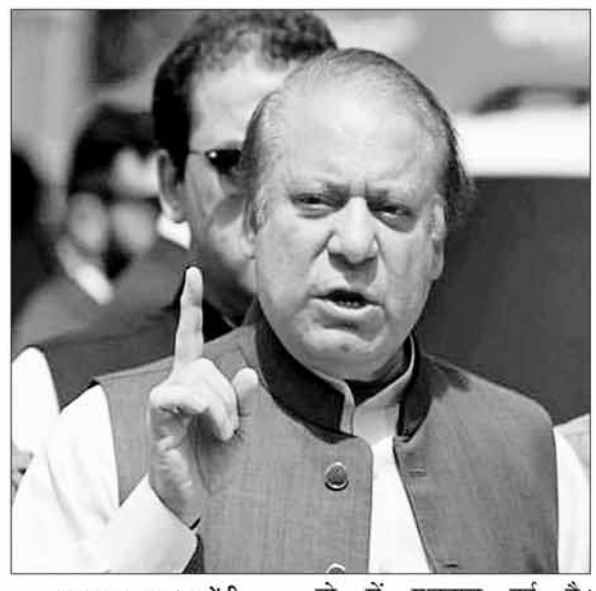

« इस्लामाबाद। एजेंसी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लगे आरोपों की जांच कर रही पनामागेट की संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने 15 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की है। इसमें पांच केस पर फैसला लाहौर हाई कोर्ट पहले ही सुना चुकी है, जबकि 8 मामलों में शरीफ के खिलाफ जांच और दो में पूछताछ हुई है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इन 15 केसों में तीन 1994 से 2011 के बीच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यकाल के हैं, जबकि 12 मामले जनरल परवेज मुशर्रफ के समय के हैं जब शरीफ का तख्तापलट कर जनरल ने अक्टूबर 1999 में कमान संभाल ली थी। बता दें कि इनमें शरीफ परिवार से जुड़ा 18 साल पुराना लंदन में प्रॉपर्टी मामला भी शामिल है। दिसंबर 1999 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा शुरू किए गए आठ जांचों में शरीफ परिवार के चार लंदन अपार्टमेंट के बारे में मामला भी था। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को लंदन में फ्लैट से जुड़े मामले की जांच करने को कहा था। जेआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कई मामलों की विस्तृत जांच के बिना ही उसे बंद कर दिया गया। शरीफ परिवार पर धन जुटाने के मामले में जेआईटी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं। जेआईटी ने यह भी सिफारिश की है कि एनएबी को लंदन संपत्तियों की जांच को पूरा करने के निर्देश दिए जाए। जेआईटी ने 1990 के दशक के उन मामलों की जांच की भी अनुशंसा की है जिसमें उन पर एफआईए (फेडरन इंवेस्टीगेशन एजेंसी) गलत तरीके 42 लोगों की नियुक्तियों का आरोप है।

आतंकी हमले ईरानी क्षेत्र में घुसे आतंकी दस्ते ने दो नागरिकों को मार डाला और दो को घायल कर दिया

ईरान में आतंकी हमले कराने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान

« तेहरान। एजेंसी

पाकिस्तान अब भारत और अफगानिस्तान के बाद ईरान पर भी आतंकी हमले करा रहा है। पाकिस्तान से सीमा पार करके ईरानी क्षेत्र में घुसे आतंकी दस्ते ने दो नागरिकों को मार डाला और दो को घायल कर दिया। यह जानकारी ईरान की सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी वेबसाइट ने बयान जारी कर कहा है, शनिवार को ईरान के सीमा क्षेत्र सारावान में पाकिस्तानी आतंकियों ने फायरिंग करके मजदूरी करने वाले दो लोगों की हत्या कर दी। यह इलाका सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है। जवाबी कार्रवाई में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक हमलावर को मार गिराया, जबकि दो को घायल कर दिया। आतंकी दस्ते में शामिल बाकी के हमलावर पाकिस्तानी क्षेत्र में भागने में सफल रहे। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, मगर इलाके में जैश अल-आदिल संगठन के हमलों का वर्षों पुराना इतिहास है। यह संगठन अल-कायदा से जुड़ा हुआ है और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। इससे पहले इस आतंकी संगठन ने अप्रैल महीने में दस ईरानी सीमा रक्षकों की मिरजावेह प्रांत में हत्या कर दी थी। 19 जून को ईरान के बंदरगाह वाले शहर चाबहार में हमले की नीयत से आए आतंकी संगठन अंसार अल-फुरकान के सरगना और चार सदस्यों को पहचान कर गार्ड्स ने उन्हें मार डाला था। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीमा पर आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।

लीबिया में बेनगाजी हवाईअड्डे को 3 साल बाद खोला गया

» **त्रिपोली।** लीबिया के शहर बेनगाजी में संघर्ष के कारण तीन साल तक बंद रहे बेनगाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को भारी सुरक्षा के बीच वाणियिक उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को बेनिना हवाई अड्डे से पहली उड़ानें राजधानी त्रिपोली, अम्मान और लीबिया के शहर कुफरा के लिए संचालित की गई। ट्यूनिस, इस्तांबुल, एलेक्जेंड्रिया और लीबिया के जिंटान तक जाने और वहां से आने के लिए भी उड़ानें संचालित होंगी।